



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]
No. 275]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 2004/फाल्गुन 27, 1925
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 2004/PHALGUNA 27, 1925

पोत परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2004

का.आ. 366(अ).—अतः माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय, ने रिट याचिका सं. 2003 की 1574, नारायण चंद्र दास बनाम संघ सरकार एवं अन्य में 4 फरवरी, 2004 को यह निर्देश दिया है कि वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 के तहत एक अधिकरण गठित किया जाए तथा श्री नारायण चंद्र दास द्वारा इस संबंध में उठाए गए विवाद को उस अधिकरण को सौंपा जाए।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा एक अधिकरण का गठन करती है, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में होगा और याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गये विवाद को सौंपती है और श्री के. के. बेहरा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पश्चिम बंगाल, 1985) को उक्त अधिकरण में नियुक्त करती है, जो सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 1 माह के भीतर केन्द्र सरकार को अधिकरण का अधिनिर्णय प्रस्तुत करेगा। उक्त अधिकरण को सौंपे गए विचारार्थ विषय और शर्तें अधोलिखित अनुसूची में दी गई हैं।

अनुसूची

(क) विचारार्थ विषय

श्री नारायण चंद्र दास द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 2003 की 1574 को अभ्यावेदन के रूप में जांच करना तथा वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 के तहत आदेश देना।

(ख) शर्तें

- अधिकरण का मुख्यालय कलकत्ता में होगा और इसे सचिवालय सहायता, शिपिंग मास्टर, मरकन्टाइल मैरीन डिपार्टमेंट, कलकत्ता द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- अधिकरण द्वारा कार्यवाही करने पर तथा टी.ए./डी.ए. के रूप में होने वाला व्यय तथा अन्य सम्बद्ध व्यय मरकन्टाइल मैरीन डिपार्टमेंट, कलकत्ता द्वारा यात्रा व्यय और कार्यालय व्यय शीर्ष से वहन किया जाएगा।
- अधिकरण, किसी व्यक्ति अथवा किसी श्रेणी के नाविक, अथवा नाविकों के किसी संघ, याचिकाकर्ता श्री नारायण चंद्र दास तथा भारतीय नौवहन निगम लि., जिस पर याचिकाकर्ता का आरोप है कि उनके जहाज पर से मास्टर ने उसे समझौता नियम के अन्तर्गत कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उतार दिया था, के प्रतिनिधियों को साक्ष्य देने और विचारार्थ विषय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से बुला सकता है। अधिकरण, यदि चाहे तो उन पदाधिकारियों को भी, जो नेशनल मैरीटाइम बोर्ड के समझौते तय कराने में शामिल होते हैं, स्पष्टीकरण, रिकार्ड्स की प्रस्तुति हेतु, अथवा किसी अन्य वांछित सूचना हेतु, अधिकरण की कार्यवाही के दौरान बुला सकता है।
- एक सदस्यीय अधिकरण के अध्यक्ष को एक बैठक भत्ता दिया जाएगा और वह नियमों के तहत देय टी.ए./डी.ए. के लिए भी पात्र होगी। (व्याख्या—एक बैठक—प्रत्येक बार एक बैठक पांच घंटे से कम नहीं होगी)।

(1)

(v) अधिकरण की कार्यविधि का निर्णय करते हुए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभ्यावेदन पर शीघ्रतिशीघ्र विचार किया जाए। बेहतर होगा यह कार्यवाही उनके आदेश की तारीख अर्थात् 4 फरवरी, 2004 से 8 सप्ताह के अन्दर पूरी कर ली जाए। अधिकरण के गठित होने के एक माह के भीतर अधिकरण द्वारा सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी।

[फा. सं. एस. आर.-11014/1/2004-एम.ए.]

सुशील कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2004

S.O. 366(E).—Whereas the Hon'ble High Court of Calcutta, *vide* order dated 4-2-2004 in Writ Petition No. 1574 of 2003—Shri Narayan Chandra Das Versus Union of India and others has directed that a Tribunal may be constituted under Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and refer the dispute raised by Shri Narayan Chandra Das in this regard.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 150 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal with headquarters at Kolkata and refers the dispute raised by the petitioner and appoints Shri K. K. Behra, IAS (WB, 1985) to the said Tribunal who shall submit the award of the Tribunal to the Central Government within 1 month from the date of publication of this notification in the Official Gazette. The Terms of Reference and the Terms and Conditions of said Tribunal are set out in the schedule given below.

SCHEDULE

(A) Terms of reference

To consider the Writ Petition No. 1574 of 2003 filed by Shri Narayan Chandra Das as a representation and to pass an order under Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958.

(B) Terms and Conditions

- (i) The Tribunal shall have its headquarters at Kolkata and secretarial assistance shall be provided by the Office of the Shipping Master/Mercantile Marine Department, Kolkata.
- (ii) The expenditure incurred by the Tribunal in conducting the proceedings and TA/DA and Other allied expenses shall be met out of travel and office Expenses budget of the Mercantile Marine Department, Kolkata.
- (iii) The Tribunal may invite individuals or any class of seamen or any union of seamen, the petitioner Shri Narayan Chandra Das, the representatives from M/s Shipping Corporation of India Ltd. on whose vessel the petitioner has alleged that he was signed of by the Master before completion of the term of Articles of Agreement, for giving evidence and for obtaining information relevant to the terms of reference. Tribunal may also invite such other office bearers who are involved in concluding the NMB Agreements for any clarification and production of records, information as required, during the proceeding of the tribunal.
- (iv) The chairman of the One Person Tribunal shall be paid a sitting fee and would also be entitled to TA/DA, as admissible under the rules. (*Explanation* : One sitting shall not be less than five hours on each occasion).
- (v) The term of the Tribunal has been decided by the Hon'ble High Court of Kolkata wherein it has been stated that the representation will be considered by the tribunal as early as possible preferably within 8 weeks from the date of the order i.e. 4-2-2004.

The report will be submitted by the Tribunal to the Government within 1 month from the date of its constitution.

[F. No. SR-11014/1/2004-MA]

SUSHEEL KUMAR, Jt. Secy.